



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 पौष 1932 (श0)  
(सं0 पटना 798) पटना, शुक्रवार 24 दिसम्बर 2010

---

सं0 3ए2-वे0पु0-12/2009 (भाग-II)—14303  
वित्त विभाग

संकल्प  
22 दिसम्बर 2010

विषय:—बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षण के संबंध में।

वित्त विभाग की संकल्प सं0 735, दिनांक 07 अप्रैल 2005 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन आदि का पुनरीक्षण आदि किया गया था।

2. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि के संबंध में पद्मनाभन समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि के पुनरीक्षण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि को निम्नरूपेण पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है :-

- (I) न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा:—बिहार न्यायिक सेवा के वैसे पदाधिकारी जो दिनांक 02 सितम्बर 2008 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं, के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा के बदले 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक होगा तथा 10 वर्षों की अर्हक सेवा पेंशन प्रदायी सेवा होगी। 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को सेवा-निवृत्त की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाएगी। वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारी जो सेवा-निवृत्ति की तिथि को 10 वर्षों से अधिक किन्तु 20 वर्षों से कम सेवा पूरी करते हैं उन्हें सेवा-निवृत्ति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर परिगणित पेंशन की राशि को आनुपातिक रूप से कम करके निर्धारित किया जाएगा। यह प्रावधान 02 सितम्बर 2008 से लागू होगा।
- (II) प्रभाव की तिथि:—इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान, वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामले में लागू होंगे जो 01 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं अथवा उनकी मृत्यु हुई है।
- (III) दिनांक 01 जनवरी 2006 या उसके बाद एवं दिनांक 01 सितम्बर 2008 के बीच सेवा-निवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अंतिम वेतन का 33 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पेंशन नियमावली के नियमों के

आलोक में पेंशन की गणना की जाएगी तथा उससे कम सेवा करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को आनुपातिक आधार पर पेंशन स्वीकृत किया जाएगा।

- (IV) मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान:—दि० 01 जनवरी 2006 या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सेवा-निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 3.5 लाख से बढ़ाकर 10 (दस) लाख करने का निर्णय लिया गया है।
- (V) अधिक उम्र के सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को पेंशन की राशि में वृद्धि:—बिहार न्यायिक सेवा के वैसे सेवा-निवृत्त पदाधिकारी जिन्होंने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली है उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन में निम्नांकित विवरणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा:—

| पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी का उम्र  | अतिरिक्त पेंशन की राशि                              |
|--|---|
| 80 से 85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी  | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत  |
| 85 से 90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी  | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत  |
| 90 से 95 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी  | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत  |
| 95 से 100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत  |
| 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी     | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत |

यह प्रावधान दिनांक 02 सितम्बर 2008 से लागू होगा।

(VI) पेंशनधारी एवं सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को भत्ते के मद में बकाया राशि का भुगतान दि० 31 मार्च 2011 के पूर्व किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मदन मोहन प्रसाद,  
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 798-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>